ए-45011/4/2023-समन्वय II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली, 22 दिसंबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को अक्तूबर, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अगोपनीय भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सु. सामंत
(सुश्रुत सामंत)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309- 5244

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6 मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एंड सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी 20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-II)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्ति और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (निवेश)/संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (वित्त मंत्री)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2023

ए-45011/4/2023-समन्वय II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

विषय: अक्टूबर, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

व्यापक आर्थिक अवलोकन:

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक मंदी के बीच, मजबूत घरेलू मांग से उत्साहित होकर उल्लेखनीय समुत्थानशीलता का प्रदर्शन किया है। प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की आर्थिक मजबूती पर भरोसा जताया है। जहां मूडीज ने वित्त वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष 24) के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि को 6.7 प्रतिशत पर बरकरार रखा है, वहीं फिच ने भारत के मध्यम अवधि के संभावित विकास अनुमान को 70 आधार अंक बढ़ाकर 6.2 प्रतिशत कर दिया है।

वित्त वर्ष 2024 में अर्थव्यवस्था में अब तक की आपूर्ति की स्थिति भी इस विश्वास की पुष्टि करती है। कृषि क्षेत्र में, चालू वर्ष में नवीनतम अनुमान प्रमुख खरीफ फसलों के मजबूत उत्पादन का संकेत देते हैं। रबी की बुआई में भी अच्छी प्रगति देखी गई है, जिससे मजबूत रबी उत्पादन की उम्मीद जगी है। वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान ग्रामीण मांग में क्रमिक गति बनी हुई है क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन से आय स्थिर रही है और मुद्रास्फीति का दबाव सामान्य बना हुआ है। साथ ही, बढ़ते उत्पादन और बिक्री में विस्तार से विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अनुकूल मांग स्थितियों और नए व्यवसायों की मजबूत आमद के कारण सेवाओं से संबंधित गतिविधि का भी विस्तार हो रहा है।

मांग के क्षेत्र में, निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) चालू वर्ष के दौरान भारत के विकास के सबसे मजबूत प्रेरक के रूप में उभरा है। त्यौहारी सीजन ने उपभोग मांग को और मजबूत किया है. जबकि संचित बचत और बेरोजगारी की घटती दर से उपभोग मांग में वृद्धि हुई है। इक्विटी बाजारों के बढ़ते पूंजीकरण और बढ़ती भू-संपदा की कीमतों से उत्पन्न होने वाले धन प्रभाव ने भी खपत को मजबूत किया है।

अक्टूबर 2023 के दौरान व्यापारिक निर्यात में 11 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अक्टूबर 2023 में सेवा निर्यात भी मजबूत रहा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), जो अक्टूबर 2023 में निवल विक्रेता थे, वे नवंबर 2023 की पहली छमाही में निवल खरीदार बन गए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में पर्याप्तता और रुपये में स्थिरता भारत के विदेशी क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार में और अधिक मदद करती है।

केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए बजट घाटे के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर है। विवेकपूर्ण व्यय प्रबंधन द्वारा समर्थित राजस्व संग्रह में निरंतर वृद्धि ने वर्ष की पहली छमाही के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 40 प्रतिशत के भीतर समाहित करने में सक्षम बनाया है। सरकार का पूंजीगत व्यय पर इस वर्ष के दौरान भी बल देना जारी रहा, जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिला है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हाल ही में भारी और तीव्र गिरावट ने सार्वजनिक वित्त पर संभावित प्रभाव के एक महत्वपूर्ण कारक का निवारण कर दिया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति जो सितंबर 2023 में 5 प्रतिशत से अक्टूबर 2023 में घटकर 4.9 प्रतिशत हो गई। मुद्रास्फीति में यह गिरावट मुख्य रूप से कोर (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण थी जबकि अक्टूबर 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति सितंबर 2023 के समान ही रही। कुल मुद्रास्फीति अक्टूबर 2023 में चार महीने के निचले स्तर पर थी, जबकि इसका मुख्य घटक पिछले 43 महीनों में सबसे कम था। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के रुझान से यह भी पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए प्रमुख इनपुट की लागत में भी गिरावट आई है।

हाल ही में जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में भी सकारात्मक युवा और लिंग-संबंधी रुझानों पर प्रकाश डाला गया है। वार्षिक युवा बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट के साथ-साथ श्रम बल में युवाओं की अधिक भागीदारी जनसांख्यिकीय लाभांश के बेहतर उपयोग का संकेत देती है। यह कौशल विकास में लगातार प्रगति के साथ मेल खाता है, 2015 से पीएम कौशल विकास योजना के तहत लगभग 1.4 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। लैंगिक दृष्टिकोण से, महिला श्रम बल भागीदारी दर (एफएलएफपीआर) पिछले छह वर्षों से बढ़ रही है।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) **जी20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत निम्नलिखित वित्त ट्रैक बैठकें** अक्टूबर 2023 के दौरान आयोजित की गईं:

क) जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की चौथी और अंतिम बैठक 12 से 13 अक्टूबर, 2023 तक दो दिनों में दो सत्रों में आयोजित की गई थी और इसमें "बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबी) को मजबूत करना" और "वैश्विक अर्थव्यवस्था तथा क्रिप्टो एसेट्स" के संबंध में मराकेश, मोरक्को में आईएमएफ/डब्ल्यूबी की वार्षिक बैठकों से इतर चर्चा की गई थी। बैठक की अध्यक्षता भारत के माननीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर ने संयुक्त रूप से की।

ख) एफएमसीबीजी की बैठक 11 अक्टूबर को चौथी जी20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों (एफएमसीबीजी प्रतिनिधि) की बैठक से पहले हुई थी, जिसमें प्रतिनिधियों ने जी20 विज्ञप्ति पर बातचीत की थी जिसे एफएमसीबीजी द्वारा अपनाया गया था। एफएमसीबीजी विज्ञप्ति में दो प्रमुख परिणाम निम्नलिखित थे:

- जी20 एफएमसीबीजी ने एमडीबी को मजबूत करने के संबंध में जी20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह (आईईजी) की रिपोर्ट का स्वागत किया। इसके बाद, जी20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप को एमडीबी के परामर्श से आईईजी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने और बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी एमडीबी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता सुझाने का काम सौंपा गया है, जिसमें एक प्रणाली के रूप में बेहतर ढंग से काम करने के तरीके भी शामिल हैं। उन्हें अप्रैल 2024 के लिए निर्धारित बैठक में एफएमसीबीजी को पुनः रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।
- जी20 एफएमसीबीजी ने क्रिप्टो-एसेट्स पर जी20 रोडमैप को अपनाया। आईएमएफ और एफएसबी को क्रिप्टो एसेट्स पर जी20 रोडमैप के कार्यान्वयन की प्रगति पर नियमित और संरचित अद्यतन (अपडेट) प्रदान करने का काम सौंपा गया है।

ग) जी20 एफएमसीबीजी और जी20 एफसीबीडी बैठकों से इतर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें एमडीबी की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने पर जी20 प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय सेमिनार, क्षमता निर्माण और 2-स्तंभ समाधान पर जी20-आईएमएफ उच्च स्तरीय संवाद, ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंडटेबल (जीएसडीआर) प्रिंसिपल्स की बैठक, समुत्थानशील एवं समावेशी आपूर्ति-श्रृंखला संवर्धन (आरआईएसई) हेतु भागीदारी और जी-7 अफ्रीका गोलमेज सम्मेलन का आरंभ शामिल है।

घ) माननीय वित्त मंत्री ने अपने समकक्षों (चयनित जी20 और आमंत्रित देशों के) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे, अफ्रीकी संघ, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, यूके, आईएमएफ) विश्व बैंक समूह के प्रमुखों के साथ दस द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए।

(ii) माराकेच, मोरक्को में आईएमएफ-विश्व बैंक समूह की वर्ष 2023 वार्षिक बैठक में माननीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

क) विकास समिति की पूर्ण बैठक;

ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति (आईएमएफसी) रिस्ट्रिकटिड ब्रेकफास्ट मीटिंग;

ग) आईएमएफसी पूर्ण बैठक; और,

घ) "आईएमएफ नीतिगत प्राथमिकताएं और संस्थान को अपनी सदस्यता का समर्थन कैसे करना चाहिए" पर अमेरिकी ट्रेजरी गोलमेज सम्मेलन

(iii) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं/उनमें भाग लिया गया:

क) एफएसबी संचालन समिति की बैठक 20 अक्टूबर, 2023 को हुई, जिसमें वर्ष 2024 के लिए जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों और एफएसबी कार्य प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।

ख) 37वीं अर्ली वार्निंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) की बैठक 10 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें इंटर-रेगुलेटरी वर्किंग ग्रुप (आईआरडब्ल्यूजी) के गठन, जेपी मॉर्गन के जीबीआई-ईएम ग्लोबल इंडेक्स सूट में भारत के समावेश के व्यापक आर्थिक निहितार्थ आदि पर चर्चा की गई थी।

ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 09 से 13 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित पेरिस इन्फ्रावीक में भाग लिया और भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के तहत जी20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के परिणामों को प्रस्तुत किया, जो भावी शहरों के वित्तपोषण की प्रमुख प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा था: टिकाऊ, समावेशी और लचीला।

घ) भारत-ब्रिटेन निवेश वार्ता 3 से 6 अक्टूबर, 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई।

ङ) भारत-ब्रिटेन निवेश वार्ता 13 से 17 अक्टूबर, 2023 तक लंदन, यूके में आयोजित की गई।

च) भारत-ब्रिटेन निवेश वार्ता आभासी रूप से 12 और 19 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई।

छ) द्विपक्षीय निवेश विवाद समीक्षा बैठक 20 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई थी।

(iv) इस माह के दौरान निम्नलिखित **अधिसूचना जारी की गई:**

रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर 500/- रुपये मूल्य का स्मारक सिक्का

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम सुशासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या : 06

विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में : 13